भारत का सुरक्षा परिवेश और विदेश नीति

(India's Security Environment and and Foreign Policy)

किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते समय, नीति निर्धारकों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वे ऐसी नीति का निर्माण करें जो देश की सुरक्षा तथा अर्थिक विकास का मार्ग तैयार करने में सफलता की तरफ अग्रसर हो। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत की विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय सुरक्षा के आन्तरिक व बाहरी परिवेश के सन्दर्भ में ही किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के रूप में भारत की विदेश नीति के प्रमुख ध्येय सीमाओं की सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता व सम्प्रभुता की सुरक्षा, जनता के जीवन व सम्पति की सुरक्षा व आर्थिक विकास एवं प्रगति हैं। भारत की सुरक्षा नीति घरेलु, क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश से प्रभावित होती है क्योंकि कई बार देश की सुरक्षा व्यवस्था को कई तरह से संकट उत्पन्न हो जाता है। यह खतरा देश की सीमाओं के अन्दर रहने वाली विघटनकारी ताकतों से भी हो सकता है और सीमाओं से बाहर विदेशों द्वारा प्रोत्साहित आतंकवाद या प्रत्यक्ष आक्रमण से भी। सुरक्षा परिवेश के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति सुरक्षा नीति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :-

(I) घरेलु परिवेश व भारत की सुरक्षा नीति

(Domestic Environment and India's Security Policy)

किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के अन्दर घटने वाली घटनाएं भी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। भारत को बार-बार उठने वाले अलगाववादी आन्दोलन व गतिविधियां ने विदेशी सहायता प्राप्त करके देश की एकता व अखण्डता को चुनौती दी है। जम्मू-कश्मीर व पंजाब में लम्बे समय तक जारी रहने वाली आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान द्वारा ही समर्थित रही हैं। पाकिस्तान आज भी कश्मीर में प्रशिक्षित आतंकवादी भेजकर व उन्हें आर्थिक मदद देकर प्रोकसी युद्ध को जन्म दे रहा है। इसी तरह चीन, पाकिस्तान, भूटान, बर्मा व बंगलादेश की सीमाओं से लगते राज्यों में बार-बार स्वायत्तता से उठने वाली मांगें व आन्दोलन के भी विदेशों से तार जुड़े रहे हैं। इनमें नागा आन्दोलन व मिजो आन्दोलन प्रमुख हैं। कई बार बाहरी देशों या पड़ौसी देशों की तरफ से शरणार्थी के रूप में आने वाले लोग भी विघटनकारी प्रक्रिया को जन्म दे देते हैं। 1971 में बंगलादेश से भारत में शरणार्थी के रूप में आए लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न किया था। इसी तरह तमिल शरणार्थी समस्या को लेकर भी हुआ। कई बार विघटनकारी गुटों में आपसी तालमेल भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार का तालमेल पंजाब व कश्मीर के आतंकवादी गुटों में देखने को मिला। इस प्रकार का तालमेल राष्ट्रीय

सुरक्षा की द ष्टि से पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्धों को भी प्रभावित कर देता है। इसी तरह देश मे कमजोर केन्द्रीय सरकारें व केन्द्र तथा राज्य सरकारों में तालमेल क अभाव भी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसा ही देश की कमजोर आर्थिक स्थिति व सामाजिक समरसता अभाव के कारण भी होता है। 1947 से 1974 तक भारत की सुरक्षा नीति के कमजोर रहने के पीछे भारतीय अर्थ-व्यवस्था का पिछड़ापन व आत्मनिर्भरता का अभाव ही था। इस तरह देश की घरेलु परिस्थितियां भी सुरक्षा नीति व विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। पिछली सदी के अन्त में देश की मजबूत आर्थिक व्यवस्था व राजनीतिक सिरिता के कारण भारत की विदेश नीति भी काफी मजबूत हुई है। अब भारत सरकार रक्षा नीति को व्यावहारिक रूप देने में पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में सक्षम है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी भारत में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ने से ही भारत अपनी सुद ढ़ आर्थिक व सामरिक विदेश नीति बनाने में सफल हुआ है।

(II) क्षेत्रीय परिवेश व भारत की सुरक्षा नीति

(Regional Environment and India's Security Policy)

भारत की सुरक्षा नीति पर क्षेत्रीय परिवेश अर्थात् पास-पड़ोस के देशों द्वारा उत्पन्न परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि भारत की सुरक्षा नीति क्षेत्रीय परिवेश के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। क्षेत्रीय परिवेश में चीन, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्य, खाड़ी देश, इन्डोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड, सिंगापुर, हिन्द महासागर का क्षेत्र शामिल है। इनमें से चीन, पाकिस्तान तथा हिन्द महासागार के घटनाक्रम का भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। 1962 के चीनी आक्रमण, चीन का परमाणु क्षेत्र में भारत से शक्तिशाली होना व चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु कार्यक्रमों में सहयोग देना भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गम्भीर चुनौती रहा है।

यद्यपि भारत चीन व पाकिस्तान के साथ प्रारम्भ से ही सम्बन्ध सुधारने के प्रयास करता रहा है, लेकिन फिर भी 1962 में चीन ने तथा 1965, 1971 तथा 1999 में पाकिस्तान ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। हिन्दी चीनी-भाई भाई की बात करने वाला भारत भी 1962 में चीनी आक्रण को रोकने में नाकाम रहा। चीन द्वारा तिब्बत व पाक अधिकृत कश्मीर के कुछ भागों में सड़क मार्गों के विकास ने भारत को सामरिक द ष्टि से कमजोर किया है। इस युद्ध में जीता हुआ हजारों मील क्षेत्र आज भी चीन के कब्जे में है। तिब्बत व सीमा-विवाद को लेकर दोनों देशों में चलने वाला लम्बा संघर्ष भारत की सुरक्षा के लिए सिरदर्द बना रहा है। भारत के कुछ पड़ोसियों का उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार, चीन की भारत विरोधी नीति का ही एक हिस्सा रहा है। पिछली सदी के अन्त तक चीन की भूमिका भारत की शक्ति को सीमित करने वाली रही है। चीन ने बर्मा में सैनिक शासकों को समर्थन दिया और भारतीय लोकतन्त्र को चुनौती पेश की। चीन ने पाकिस्तान के साथ भी सन्धि करके उससे पाक-अधिकृत कश्मीर का कुछ हिस्सा प्राप्त किया और बेलेस्टिक प्रक्षेपास्त्र भी पाकिस्तान को दिये। 1996 में इस बात की भी सूचना मिली कि चीन एक प्रक्षेपास्त्र कारखाना स्थापित करने में पाकिस्तान को मदद दे रहा है। चीन की तरह पाकिस्तान भी भारत विरोधी नीति अपनाता रहा है। 1980 के दशक में पाक द्वारा पंजाब में आतंकवाद तथा उसके बाद 1990 के दशक में कश्मीर में फैलाया गया आतंकवाद इसी बात की ही पुष्टि करता है। 1987 में पाकिस्तान द्वारा परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। 1990 के दशक में पाकिस्तान को चीन, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अमेरिका से मिलने वाले प्रक्षेपास्त्रों के कारण यह स्थिति और अधिक गम्भीर हो गई है। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में स्वदेशी 'हल्फ मिसाईल' का परीक्षण करने से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक खतरा पैदा हो गया है। प्रतिदिन सीमा पार से होने वाली घुसपैठ व आतंकवादी गतिविधियां इसे असुरक्षा की भावना से परिपूरित ही करती है। यद्यपि भारत ने शिमला व लाहौर समझौते के द्वारा दोनों